भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

आपराधिक अपीलीय अधिकार क्षेत्र

दाण्डिक अपीलीय सं संख्या 593/ 2021

[2018 की एसएलपी (सीआरएल) संख्या 1605 से उत्पन्न]

इंद्रा देवी - अपीलकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य और अन्य - प्रतिवादी

के साथ

दाण्डिक अपीलीय संख्या 594/2021

[एसएलपी (सीआरएल) संख्या 5015/2021 से उत्पन्न]

डी संख्या 7196/2019

राजस्थान राज्य - अपीलकर्ता

बनाम

योगेश आचार्य - प्रतिवादी

निर्णय

संजय किशन कौल, जे.

1. भारतीय दंड भा.दं.सं. की धारा 420, 467, 468, 471, 120बी और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)

अधिनियम की धारा 3 (1) (4)/3 (15)/3 (5) के तहत पी. एस. बाड़मेर में दर्ज प्राथमिकी संख्या 80 में अपीलकर्ता इंद्रा देवी शिकायतकर्ता हैं। यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने और उनके पति भंवर लाल ने राजस्थान के जबलपुर जिले में खसरा संख्या 1179/03 में दो भूखंड खरीदे। इन दो प्लाटों में से एक प्लाट मेघराम को बेचा गया था जबकि दूसरा प्लाट चेतन चौधरी को बेचा गया था। उसके पति के नाम पर खरीदे गए प्लॉट में, एक आवासीय घर और दुकानें बनाई गई थीं। मेघराम पर आरोप है कि उसने धोखाधड़ी के इरादे से समझौते के साथ छेड़छाड़ की और उसे मनगढ़ंत बनाया। यह कथित तौर पर नगर पालिका के तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी सुरेंद्र कुमार माथुर और संबंधित क्लर्क और अन्य लोगों की मिलीभगत से किया गया था, जो शिकायतकर्ता और उसके पति द्वारा कब्जा किए गए जमीन और घर को हड़पने के इरादे से उसे बेच दिया गया था। खसरा नंबर को 1179/03 से बदलकर 1143/04 कर दिया गया है। यह तथ्य शिकायतकर्ता के संज्ञान में तब आया, जब उन्हें अदालत के नोटिस के साथ तामील हुआ । जब वे घर और दुकान के साथ प्लॉट के भौतिक कब्जे में थे और उनके पति कैंसर के इलाज के लिए जयपुर गए थे, तब उन्हें इस प्रकार, आरोपी व्यक्तियों ने धोखे से अनुसूचित जाति की महिलाओं को बेघर कर दिया। यह नोट किया जा सकता है कि इसमें प्रतिवादी नं. 2, योगेश आचार्य का नाम प्राथमिकी में नहीं था, लेकिन, जाहिर है, उसे संबंधित क्लर्क कहा गया है ।

2. जांच के अनुसरण में, मेघाराम के विरुद्ध एक आरोप पत्र दाखिल किया गया और दिनांक 10.04.2012 के आदेश द्वारा आरोप विरचित किए गए। प्रतिवादी नं. 2 का नाम भी आरोप-पत्र में नहीं था, लेकिन

मेघराम द्वारा सह-अभियुक्त व्यक्तियों के साथ मिलीभगत से कार्य करने का संदर्भ दिया गया था ।

3. हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए अभिलेखों में यह प्रतिबिंबित नहीं होता है कि प्रतिवादी नं. 2 को वास्तव में कैसे जोड़ा गया था, लेकिन यह कहने के लिए पर्याप्त है, कि प्रतिवादी नं. 2 ने निचली निचली अदालत के समक्ष सीआरपीसी की खंड 197के तहत एक आवेदन दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि वह एक लोक सेवक था और उसने विवादित पट्टे के आवंटन के संबंध में, जिसे मेघराम के पक्ष में निष्पादित किया गया था, जो भी किया था वह अपने आधिकारिक कर्तव्य के दौरान किया और इस प्रकार वह उपर्युक्त प्रावधान के तहत संरक्षण का हकदार था । उन्होंने आरोप पत्र पर भी हमला करने की मांग की क्योंकि यह सीआरपीसी की खंड 197 के तहत सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना दायर किया गया था।

4. निचली निचली अदालत ने दिनांक 10.08.2017 के आदेश द्वारा आवेदन को खारिज कर दिया, यह देखते हुए भी कि प्रतिवादी नं. 2 का प्राथमिकी में उल्लेख नहीं किया गया था। निचली निचली अदालत का विचार था कि यदि प्रतिवादी नं. 2द्वारा सक्षम अधिकारियों के संज्ञान में विसंगतियां लाई गई होती, तो विवादित पट्टा जारी नहीं किया गया होता। ऐसा करने में विफलता के परिणामस्वरूप जाली पट्टा तैयार किया गया। प्रतिवादी नं. 2ने भी विवादित पट्टे का मसौदा तैयार किया था जिसमें वह आवश्यक विवरण का उल्लेख करने में विफल रहा था.इस प्रकार, यह राय व्यक्त की गई कि प्रतिवादी नं. 2पर जाली पट्टा प्राप्त करने के लिए आपराधिक अपराध करने के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। प्रतिवादी नं. 2ने जो किया वह अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में

लोक सेवक द्वारा नहीं किया गया और इस प्रकार सीआरपीसी की खंड 197के तहत संरक्षण उसकी मदद नहीं करेगा।

5. इसके बाद प्रतिवादी नं. 2 ने एक आपराधिक मामला दायर किया।भारतीय दंड संहिता की खंड 482 के तहत निचली निचली अदालत के इस आदेश की आलोचना करते हुए जोधपुर स्थित उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 3138/2017 दाखिल की गई है। उच्च न्यायालय ने दिनांक 03.10.2017 के आक्षेपित आदेश द्वारा याचिका को स्वीकार कर लिया। यह राय व्यक्त की गई कि मामला देवी दान बनाम राजस्थान राज्य वाले मामले के समान था। उच्च न्यायालय ने कहा था कि स्टेशन हाउस ऑफिसर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने/दर्ज करने में विफल रहने और अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किए गए अन्य आपराधिक कार्यों के लिए मुकदमा चलाने से पहले सीआरपीसी की खंड 197 के तहत मंजूरी की आवश्यकता होती है। उक्त निर्णय से व्यथित शिकायतकर्ता ने विशेष अनुमति याचिका दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। राज्य ने एक एसएलपी भी दायर की है। दोनों मामलों में अनुमति दी गई थी।

6. अपीलकर्ता ने हमारे समक्ष प्रतिवाद किया कि प्रतिवादी नं.2की संलिप्तता केवल जांच के दौरान ही प्रकाश में आई थी। वह अनियमितताओं को अपने वरिष्ठों के संज्ञान में लाने में विफल रहे थे, जो जाली पट्टा जारी करने में सहायक थे। इस प्रकार, उसने जालसाजी को बेईमानी से छिपाने के लिए अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साजिश रची थी, और जानबूझकर आदेश पत्र पर कार्यवाही की तारीख का उल्लेख नहीं किया था। जाली दस्तावेजों की इस तरह की कार्रवाई को उसके आधिकारिक कर्तव्यों के दौरान किए गए कार्य के रूप में नहीं

माना जाएगा और इस प्रकार सीआरपीसी की खंड 197 प्रतिवादी संख्या 2 को सुरक्षा नहीं देगी।

7. दूसरी ओर, प्रतिवादी नं. 2ने उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय का समर्थन करने का प्रयास करते हुए इस बात पर जोर दिया कि प्राथमिकी में केवल मेघराम और कुछ अज्ञात अधिकारियों का उल्लेख किया गया था.नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी सुरेंद्र कुमार माथुर ने एक याचिका दायर की थी। उसी लेनदेन से संबंधित सीआरपीसी की धारा 482 के तहत और उच्च न्यायालय ने 22.02.2018 के आदेश के तहत सीआरपीसी की धारा 197 के तहत उन्हें सुरक्षा प्रदान की थी। उनके आद्याक्षर लगाने का आचरण उनके कर्तव्यों के निर्वहन में किया गया कार्य माना गया था। इसी तरह, संदीप माथुर, एक जूनियर इंजीनियर, जो उसी लेन-देन का हिस्सा थे, को सत्र न्यायालय द्वारा 19 मार्च 2020 के आदेश द्वारा एक बार फिर उसी प्रावधान के तहत सुरक्षा प्रदान की गई, यानी सीआरपीसी की धारा 197 के तहत। शिकायतकर्ता और राज्य द्वारा दोनों आदेशों को चुनौती नहीं दी गई। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी नं. 2 केवल अपना आधिकारिक कर्तव्य निभा रहा था, जो उसे आवंटित किए गए कार्य से स्पष्ट है जो कृषि भूमि के आवंटन, नियमितीकरण, रूपांतरण और भूमि और रूपांतरण से संबंधित सभी प्रकार के कार्यों से संबंधित था । मेघराम का आवेदन कार्यालय द्वारा से भेजा गया था और कार्यवाही से पता चलता है कि फाइल शुरू में कार्यकारी अधिकारी के समक्ष रखी गई थी, जिन्होंने निरीक्षण का निर्देश दिया था, जो जूनियर इंजीनियर द्वारा किया गया था।इसके बाद फिर से कार्यकारी अधिकारी के समक्ष फाइल रखी गई और उसके बाद ही नगर आयुक्त द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए गए। इस प्रक्रिया में शामिल दो प्रमुख लोगों को पहले ही संरक्षण प्रदान कर दिया

गया था और इस प्रकार इसमें प्रतिवादी नं. 2, जो केवल एक लोअर डिवीजन क्लर्क था, को समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता था ।

8. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने **बी साहा बनाम एमएस कोचर अन्य (1979) 4 एस. सी. सी. 177 और महाराष्ट्र राज्य बनाम डॉ. बुधिकोटा सुब्बाराव (1993) 3 एस. सी. सी. 339** में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया। का और तर्क दिया कि सीआरपीसी की धारा 197 को लोक सेवक को उन कार्यों के संबंध में सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक उदार अर्थ में पढ़ा जाना चाहिए, जो हालांकि एक अपराध का गठन करते हैं, उनके आधिकारिक कर्तव्यों से "सीधे और उचित"जुड़े हुए हैं ।

9. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की प्रस्तुतियों पर विचार किया है। सीआरपीसी की खंड 197 किसी अधिकारी को अनावश्यक उत्पीड़न से बचाती है, जो अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किए गए अपराध का आरोपी है और इस प्रकार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना अदालत को ऐसे अपराध का संज्ञान लेने से रोकती है।लोक सेवकों को दुर्भावनापूर्ण या तंग आदेश वाले अभियोजन से बचाने के लिए उन्हें एक विशेष श्रेणी के रूप में माना गया है।साथ ही, ढाल भ्रष्ट अधिकारियों की रक्षा नहीं कर सकती और प्रावधानों का अर्थ इस तरह से लगाया जाना चाहिए कि ईमानदारी, न्यायाधीश और सुशासन के उद्देश्य को आगे बढ़ाया जा सके।(देखें सुब्रमण्यम स्वामी बनाम मनमोहन सिंह (2012) 3 एस. सी. सी. 64)। अधिकारियों द्वारा धोखाधड़ी, अभिलेखों के निर्माण या दुर्विनियोजन में कथित संलिप्तता को उनके आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में नहीं कहा जा सकता है। तथापि, ऐसी मंजूरी आवश्यक है यदि लोक सेवक के विरुद्ध अभिकथित

अपराध उसके द्वारा अपने शासकीय कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करते समय किया गया है या कार्य करने के लिए तात्पर्यित है और आदेश में यह पता लगाने के लिए कि क्या अभिकथित अपराध उसके शासकीय कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करते समय किया गया है या कार्य करने के लिए तात्पर्यित है, तो अनुसरण किए जाने वाले मापदंड का प्रथमदृष्टया यह मत बनाना है कि क्या लोप के कृत्य का, जिसके लिए अभियुक्त को अपने कर्तव्यों के निर्वहन के साथ युक्तियुक्त संबंध था।(देखें महाराष्ट्र राज्य बनाम डॉ. बुधिकोटा सुब्बाराव)। इसलिए, वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या किया गया कार्य सीधे तौर पर आधिकारिक कर्तव्य से संबंधित है।

10. हमें वर्तमान मामले के तथ्यों पर पूर्वोक्त परीक्षण लागू करना होगा।इस संबंध में, प्राथमिकी में नाम न होने का प्रतिवादी नं. 2का तथ्य बहुत महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि कथित भूमिका बाद में प्रकाश में आई.हालांकि, जो बात महत्वपूर्ण है वह कथित उल्लंघन में उन्हें सौंपी गई भूमिका है, यानी अपने वरिष्ठों के साथ साजिश।इससे यह पता चलता है कि जहां तक कागजात की प्रोसेसिंग का सवाल है, कार्यकारी अधिकारी सुरेंद्र कुमार माथुर ने अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान आयोजित प्रासंगिक कागजातों में अपने लघु हस्ताक्षर कर दिए थे। इतना ही नहीं, कथित लेनदेन का हिस्सा रहे संदीप माथुर को भी इसी तरह की सुरक्षा प्रदान की गई थी। प्रतिवादी नं. 2को जो कार्य सौंपा गया था, वह कृषि भूमि के आवंटन, नियमितीकरण, रूपांतरण से संबंधित था और उसके कार्य क्षेत्र में आता था.मेघाराम के आवेदन की प्रक्रिया में, फाइल को शुरू में कार्यकारी अधिकारी के पास रखा गया, जिन्होंने निरीक्षण का निर्देश दिया और निरीक्षण जूनियर इंजीनियर द्वारा किया गया और उसके बाद ही नगर आयुक्त ने फाइल पर

हस्ताक्षर किए। परिणाम यह है कि वरिष्ठ अधिकारियों, जिन्होंने फाइल के साथ काम किया है, को सुरक्षा प्रदान की गई है जबकि लिपिक, जिसने कागजी काम किया है, अर्थात् प्रतिवादी नं. 2, को निचली निचली अदालत द्वारा समान सुरक्षा से इंकार कर दिया गया है, भले ही आरोप वास्तव में अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साजिश रचने का है.न तो राज्य ने और न ही शिकायतकर्ता ने इन दो अन्य अधिकारियों को सीआरपीसी की धारा 197 के तहत दी गई सुरक्षा के खिलाफ अपील की।

11. इस प्रकार, हम यह समझने में समर्थ नहीं हैं कि प्रतिवादी संख्या 2 को एक समान संरक्षण क्यों नहीं दिया जाना चाहिए जैसा कि क्रमशः ट्रायल कोर्ट और उच्च निचली अदालत द्वारा अन्य दो अधिकारियों के मामले में किया गया था।संज्ञान लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी की आवश्यकता होगी और किसी भी अधिकारी के संबंध में कोई मंजूरी प्राप्त नहीं की गई थी।इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अन्य दो अधिकारियों के संबंध में कार्यवाही रद्द कर दी गई थी और उच्च न्यायालय ने वर्तमान मामले में भी यही निर्देश दिया है.

12. पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपीलों को पक्षकारों को अपने स्वयं के खर्चे वहन करने के लिए छोड़ते हुए खारिज कर दिया जाता है।

जे. [संजय किशन कौल]

जे. [हेमंत गुप्ता]

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2021

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS with the help of Translators)

Disclaimer:- The translated judgment in vernacular language is made for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purposes. For all practical and official purpose, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.